

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
02.04.2025 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 5210 का उत्तर

बागपत में रेलवे संपर्क

5210. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार बागपत जिले में रेलवे संपर्क सुधारने के लिए कोई योजना बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का क्षेत्रीय सम्पर्क में सुधार के लिए नई यात्री रेलगाड़ियां अथवा मालगाड़ियां शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त जिले में रेलवे नेटवर्क में अवसंरचना संबंधी कमियों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त जिले में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या विभिन्न कदम उठाए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का विचार यात्रियों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उक्त जिले से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) रेल नेटवर्क जिलों की सीमाओं के आर-पार फैला होता है। तदनुसार, गाड़ियां नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार ऐसी सीमाओं के आर-पार शुरू की जाती हैं। बागपत जिले में मुख्य रूप से बागपत रोड, बड़ौत, मोदीनगर आदि स्टेशन हैं जो दिल्ली-सहारनपुर रेलखंड पर स्थित हैं।

वर्तमान में, बागपत रोड, बड़ौत और मोदीनगर स्टेशनों को क्रमशः 12 जोड़ी, 13 जोड़ी और 13 जोड़ी रेलगाड़ियों द्वारा सेवित किया जा रहा है जो दिल्ली, हरिद्वार, सहारनपुर आदि

शहरों को सीधा संपर्कता प्रदान करती हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल पर यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन रेलगाड़ी सेवाओं की शुरुआत और मौजूदा रेलगाड़ियों की फेरे में वृद्धि सतत् प्रक्रियाएं हैं।

#### रेल परियोजनाएं

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/जिला-वार नहीं, बल्कि जोन-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को स्वीकृति देना भारतीय रेल की एक सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्ग, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी सहित सामाजिक-आर्थिक महत्व के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं की देयता, निधि की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली ₹92,001 करोड़ की लागत वाली कुल 5,874 किलोमीटर लंबाई की 68 रेलवे परियोजनाएं (16 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 49 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,313 किलोमीटर लंबाई कमीशन हो गई है और मार्च 2024 तक 28,366 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	16	1740	297	8672
आमान परिवर्तन	3	261	0	26
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	49	3873	1016	19668
कुल	68	5874	1313	28366

उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रुपए/प्रति वर्ष
2025-26	19,858 करोड़ रुपए (लगभग 18 गुना)

वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-24 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	996 कि.मी.	199.2 कि.मी./वर्ष
2014-24	4,902 कि.मी.	490.2 कि.मी./वर्ष (2 गुना से अधिक)

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/ अंशतः आने वाली कुल 6,443 किलोमीटर लंबाई के 110 सर्वेक्षण (दोहरीकरण, नई लाइनें) स्वीकृत किए गए हैं।

#### ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी निर्माण कार्य

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 210 करोड़ रुपए की लागत से 05 ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना निर्माण और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, समपार (एलसी) के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्यों को स्वीकृति देना भारतीय रेल की सतत और गतिशील प्रक्रिया है। रेल परिचालन में संरक्षा पर इसके प्रभाव, रेलगाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (फरवरी 2025) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (फरवरी 25)	12,977 अदद

01.02.2025 तक, भारतीय रेल पर 97,422 करोड़ रूपए की लागत से 4,344 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना निर्माण और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

#### स्टेशन सुधार/ पुनर्विकास कार्य

उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत संसदीय क्षेत्र में स्थित मोदीनगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किया गया है। मोदीनगर स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं तथा स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, एकजीक्यूटिव लाउंज, लिफ्ट और सीढ़ी के साथ पैदल पार पुल, प्रवेश द्वार प्रांगण, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, परिसंचारी क्षेत्र आदि का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले में स्थित रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के कई कार्य पूरे/शुरू किए गए हैं। गोत्रा, फखरपुर, सुनेरा, अहेरा, सूजरा, बरका, बावली, अलावलपुर इदरीसपुर, बुद्धपुर और असारा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का काम पूरा हो चुका है और खेकड़ा और कासिमपुर खीरी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का काम शुरू किया गया है।

बागपत रोड और खेकड़ा स्टेशनों पर मिनी प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, परिसंचारी क्षेत्र में सुधार, पैदल पार पुल को कवर करने का काम आदि का काम पूरा हो चुका है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1337 स्टेशनों को विकास के लिए चिह्नित किया गया है, जिनमें से 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा केंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग, अकबरपुर जंक्शन, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर, आंवला, अयोध्या धाम, आजमगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदायूँ, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराइच, बलिया, बालामऊ,

	<p>बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जंक्शन, बरेली जं., बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम कर्वा, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदारनगर, इटावा जं., फरुखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, गौरीगंज, घाटमपुर, ग़ाज़ियाबाद, ग़ाज़ीपुर सिटी, गोला गोकरननाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह, इज्जतनगर, जंधई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज, कासगंज, काशी, खलीलाबाद, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, खोरसनरोड, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग एवं जंक्शन), लखनऊ सिटी, मगहर, महोबा, मैलानी, मैनपुरी जं., मल्हौर जं., मानकनगर जं., मानिकपुर जं., मरियाहू, मथुरा, मऊ, मेरठ सिटी, मिर्जापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जं., निहालगढ़, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जं., फूलपुर, पीलीभीत, पोखरायां, प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज, पं. दीन दयाल उपाध्याय, रायबरेली जं., राजा की मंडी, रामघाट हॉल्ट, रामपुर, रेनुकूट, सहारनपुर जं., सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जं., शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जं., शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जं., सोनभद्र, श्री कृष्ण नगर, सुल्तानपुर जं., सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जं., उझानी, ऊचाहार, उन्नाव जं., उत्तरेटिया जं., वाराणसी कैंट. वाराणसी सिटी, विद्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई, व्यासनगर, जाफराबाद</p>
--	--

उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। उपरोक्त कुछ स्टेशनों पर प्रगति निम्नानुसार है:

- अयोध्या धाम स्टेशन पर स्टेशन भवन, रुफ प्लाजा, कर्मचारी क्वार्टर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, भूमिगत पानी की टंकी, परिसंचरण क्षेत्र का विकास, पार्किंग क्षेत्र, पहुंच मार्ग, प्रवेश द्वारों का निर्माण, शौचालय ब्लॉक,

प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार आदि का कार्य पूरा हो चुका है और कमीशन किया जा चुका है।

- लखनऊ चारबाग स्टेशन पर, दूसरे प्रवेश वाले स्टेशन भवन (जी+6) का संरचनात्मक कार्य 5वीं मंजिल तक पूरा हो चुका है तथा इसके अलावा, संरचनात्मक कार्य, चिनाई कार्य और फिनिशिंग कार्य शुरू किए गए हैं। यात्रा टिकट परीक्षकों (टीटीई) के लिए विश्राम गृह और स्टोर डिपो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा एयर कॉन्कोर्स का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
- प्रयागराज स्टेशन पर ऊपरी पैदल पार पुल संख्या 2, पार्सल भवन, आगमन भवन और बेसमेंट प्लाजा (सिविल लाइन की तरफ) के विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है और दूसरे प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का निर्माण, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान आदि का कार्य शुरू किया गया है।
- गाजियाबाद स्टेशन पर दोनों तरफ स्टेशन भवन का निर्माण, ऊपरी पैदल पार पुल, एयर कॉन्कोर्स, थू रूफ, स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारी क्वार्टरों का संरचनात्मक कार्य, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल भवन आदि का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
- सहारनपुर जंक्शन स्टेशन पर स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, एक्जीक्यूटिव लाउंज, शौचालय, परिसंचरण क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, पहुंच मार्ग, फुटपाथ, लैंडस्केपिंग, प्रवेश द्वार, प्रवेश/निकास द्वार, संकेतक, प्रवेश रैंप का प्रावधान आदि के सुधार कार्य पूरे हो चुके हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुर लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय

उत्पादों के लिए क्योस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों ओरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडॉल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी संकल्पना की गई है।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/उन्नयन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकतानुसार किए जाते हैं, जो परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अधीन हैं। स्टेशनों के विकास/उन्नयन के लिए कार्यों को स्वीकृति देने और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत स्टेशनों के विकास/उन्नयन कार्य को सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार। उत्तर प्रदेश राज्य पांच ज़ोनों अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इन जोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 4,188 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आबंटन किया गया है।

\*\*\*\*\*